

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ (र.क.)

ब डूजलास - पंकज गढ़वाल R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या - 487/2018

निर्णय दिनांक - 13-10-2020

कासम खौं पुत्र मुनीर खौं जाति कायम खानी निवासी कस्बा राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला र.क.

प्रार्थी

बनाम

1. इस्माईल खौं पुत्र मुनीर खौं जाति चौहान निवासी बार्ड सं. 17 कस्बा राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला र.क.

2. राजस्थान सरकार जसिंह तहसीलदार साख राजगढ़ जिला र.क.

- अपापीगिण

प्रार्थना पत्र प्राप्त करने अस्पष्ट निवेद्याना अन्तर्गत -  
212 R.T.Act. व अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2  
द्वारा 151 सी.पी.सी.

अस्थित :-

1. श्री मोह सलीम खान अचिवता वास्ते - प्रार्थी
2. " महेश अग्रवाल अचिवता वास्ते अपापी सं. 1

निर्णय

उक्त से सम्बन्धित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत द्वारा 212 R.T.Act. व आदेश 39 नियम 1 व 2 द्वारा 151 सी.पी.सी. विरुद्ध अपापीगिण इस आग्रह का पेशा है कि प्रार्थी विवाहित कृषि भूमि ख. नं. 882/690 लाडादी 1.64 है रोही तहसील राजगढ़ जिला र.क. का खातेदार काश्तकार है। अपापी सं. 1 -

कर्तव्य व राजनैतिक उपाय बना कर रहे हैं जो उनके खाली स्थानों को  
 कर्तव्य बेदखल कर कब्जा करने की शक्ति में हैं तथा अपने ऐसा उपाय भी  
 कर रहे हैं जो प्रार्थी व पड़ोसियों के जानने से सफल नही हो सका। अतः प्रार्थी  
 के अत्याई निवेद्याज्ञा से पाबन्द किया जावे। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र के  
 अन्त में स्वयं का शपथ पत्र व जमाबन्दी की प्रति पेश की हैं। जवाब प्रार्थना  
 पत्र में प्रार्थी सं-1 ने विवादित कृषि भूमि प्रार्थी के खातेदारी के तथ्य को  
 स्वीकार करते हुए विशेष कथन में अंकित किया है कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड  
 में प्रार्थी ने राजस्व कर्मचारियों अन्वेषणियों से मिली भाव कर अपने अकेले के नाम  
 खातेदारी में दर्ज करवा ली जबकि विवादित कृषि भूमि उनकी पैतृक सम्पत्ति हैं जिसे  
 प्रार्थी व प्रार्थी सं-1 बहिस्ता बराबर काबिल काश्तकार हैं। अतः प्रार्थना पत्र खसि  
 रखा जावे। प्रार्थी सं-2 की ओर से धरोकार रखने कोई राज्य हित नहीं  
 होना जाहिर किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दोराने  
 बहस उभय पक्ष ने अपने-अपने अग्रिकवचनों के ही दोहराया हैं। अत्याई  
 निवेद्याज्ञा के प्रार्थनापत्र के निहाराण में निम्न बिन्दुओं पर विवेचन कर  
 निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित हैं।

प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त -

उपरोक्त दोनो बिन्दु परस्पर आश्रित हैं जिस कारण दोनो बिन्दुओं पर  
 एकसाथ विवेचन कर निर्णय दिया जाना उचित है। प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत  
 प्रार्थी के स्वयं के शपथ पत्र व जमाबन्दी की प्रति के अनुसार प्रार्थी विवादित कृषि  
 भूमि का एकमात्र खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थी सं-1 ने विवादित कृषि भूमि  
 पैतृक होना व उसमें अपना 1/2 हिस्सा पत्र कब्जा काश्त होना जवाब प्रार्थना  
 में अंकित किया है। अगर सिवाय स्वयं के शपथ पत्र के भूमि पैतृक होने व उसमें  
 हिस्सा पर अपना कब्जा काश्त होने से सम्बन्धित कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश न  
 किया है चूंकि प्रार्थी राजस्व रेकार्ड के अनुसार विवादित कृषि भूमि का एकमात्र खाते  
 काश्तकार हैं जिस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित होना  
 खातेदार काश्तकार के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा काहित करने  
 खातेदार को ही असुविधा होना स्वाभाविक है। अतः कारण उभय पक्ष के  
 व प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त दोनो बिन्दु प्रार्थी अपने पक्ष में साबित

अने में सफल रहा है। अतः दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णय दिया जायेगा।

अप्रतिपक्षीय दृष्टिकोण -

उपरोक्त दोनों बिन्दुओं के विवेचन के दौरान भूमि के स्वामित्व व कब्जा काश्त प्रार्थी के पक्ष में पाये गये हैं जिस कारण खातेदार काश्तकार के कब्जा काश्त में अजनबी व्यक्तित्व द्वारा बाधा कारित करनेसे खातेदार काश्तकार को ही क्षति होना स्वाभाविक है जबकि अप्रार्थी का विवादित कृषि भूमि के किसी भाग पर वहाँ का सर्वेच्य कब्जा है ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अतः यह बिन्दु प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। यह बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णय किया जाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के अनुसार असम्यक् निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में निर्णय के लिए निर्धारित तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त व अप्रतिपक्षीय दृष्टिकोण प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित पाये जाते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है व इस न्यायालय द्वारा जारी एकपक्षीय स्वयंसेवा आदेश दिनांक 12.10.2018 को मूलवाद के निर्णयत्व उलट किया जाता है। अप्रार्थी प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार से दखल नहीं दे सके।

जा करे।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2020 को मेरे द्वारा लिखा जा कर सर्वे इजलास सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
राजगढ़ (चुरू)